



Real Estate Regulatory Authority | भू-सम्पदा
Madhya Pradesh | विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

क्रमांक/१५५/रेरा/२०२०
प्रति,

दिनांक-13.02.2020

प्रबंध संचालक,
म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
जबलपुर

विषय:- भू-सम्पदा क्षेत्र की परियोजनाओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के पूर्व रेरा पंजीयन की पुष्टि कराने बाबत।

जैसे की आप जानते हैं, प्रदेश सहित देश भर में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 01 मई 2017 से प्रभावशील हो चुका है। रेरा एक्ट एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि भू-सम्पदा क्षेत्र की सभी आवासीय/व्यावसायिक परियोजना पर लागू होता है। अधिनियम के लागू होने के पश्चात् भू-सम्पदा क्षेत्र की ऐसी सभी प्रचलित/नवीन परियोजनाओं को रेरा पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक हो अथवा जिनमें 8 से अधिक इकाइयों का विक्रय किया जाना हो। ऐसी सभी परियोजनाओं को विधिक मान्यता एवं उन्हीं इकाइयों को विक्रय करने की पात्रता तभी प्राप्त होती है जब वह अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्वयं का रेरा में पंजीयन करा ले। इसके बगैर ऐसी परियोजनाएं अवैध होती हैं।

उल्लेखनीय है कि परियोजना के अवैध निर्माण होने पर जहाँ विधि की अवज्ञा होती है वही उन्के आवंटितियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विधिक और जनहित दोनों की ही दृष्टि से ऐसी सभी परियोजनाओं को रेरा पंजीयन कराना वांछनीय है।

म.प्र. विद्युत आपूर्ति कोड 2013 की विधि 4.23 के अंतर्गत बहु आवासीय काम्पलेक्स तथा विधि 4.30 के अन्तर्गत आवासीय परियोजना के द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन फार्म में रेरा पंजीयन का उल्लेख कराये जाने से विधिक अपेक्षा तथा जनहित दोनों की ही पूर्ति होगी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कृपया भू-सम्पदा क्षेत्र की रेरा अधिनियम की परिधी में आने वाली परियोजनाओं को विद्युत आपूर्ति दिये जाने के पूर्व यह पुष्टि कराये जाने का अनुरोध है कि वे रेरा में पंजीकृत है। ताकि रेरा पंजीयन नहीं करने वाली अवैध परियोजनाओं को हतोत्साहित किया जा सके।



अध्यक्ष

म.प्र.भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण